



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 147]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/VAISAKHA 22, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2016

विषय : कनाडा, चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम क्लोरेट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क संबंधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/13/2015-डीजीएडी.— गुजरात अल्कलीज एंड कैमिकल्स लि. और टीमैक क्लोरेट्स लिमिटेड (जिन्हें आगे 'याचिकाकर्ता' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष कनाडा, चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम क्लोरेट" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन (जिसे आगे याचिका भी कहा गया है) प्रस्तुत किया है।

- और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह याचिका याचिकाकर्ताओं अर्थात् मै. गुजरात अल्कलीज एंड कैमिकल्स लि. (जीएसीएल) और टीमैक क्लोरेट्स लिमिटेड (टीसीएल) (जिन्हें आगे घरेलू उद्योग भी कहा गया है) द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों के रूप में दायर की गई है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु के केवल दो उत्पादक हैं।

4. यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता न तो विचाराधीन उत्पाद के आयातक हैं और न ही वे विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। अतः याचिका घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से दायर की गई है और यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत 'योग्यता' संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं।

विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद 'सोडियम क्लोरेट' है, जो NaClO_3 रासायनिक सूत्र वाला एक अकार्बनिक यौगिक है। सोडियम क्लोरेट एक सफेद क्रिस्टलीय हाइड्रोस्कोपिक पाउडर है जो जल में आसानी से घुल जाता है। यह 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर आक्सीजन और सोडियम क्लोराइड से डिकम्पोज हो जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य वाणिज्यिक माप की इकाई किलोग्राम है। इसे भार के आधार पर उद्धरित किया जाता है और किग्रा. या एमटी में वैश्विक रूप से बेचा जाता है।

7. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अधीन उपशीर्ष 2829 11 00 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जॉच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

8. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद और संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं। संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं और ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। जॉच के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। अतः वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

संबद्ध देश

9. वर्तमान जॉच में शामिल देश कनाडा, चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ है।

सामान्य मूल्य

10. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य का दावा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क (1) (ग) के अनुसार परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर किया है। चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हुए, सामान्य मूल्य की गणना भारतीय उत्पादन के अनुसार कच्ची सामग्री, उपभोज्य वस्तुएं, सुविधाओं की उत्पादन लागत के आधार पर और सर्वोत्तम कीमतों के संदर्भ में की गई है।

11. यूरोपीय संघ और कनाडा के लिए, इन देशों में प्रचलित विद्युत की लागत को प्राकृतिक गैस के परिवर्तन पर आधारित विद्युत की कम से कम लागत के साथ उचित ढंग से सह-संबंधित करते हुए भारतीय उत्पादन लागत के अनुसार परिवर्तन के साथ अपनाया गया है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर तर्कसंगत सामान्य मूल्य के रूप में नियम 9क (1) (ग) के अनुसार संबद्ध देशों में परिकलित रूप में विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य पर विचार किया है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के लिए नियम 9(5) क के अनुसार सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

निर्यात कीमत

12. याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्यात कीमत का दावा द्वितीयक स्रोत आईबीआईएस आंकड़ों के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय मालभाड़े, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए निर्यात कीमत संबंधी समायोजनों का दावा और उल्लेख किया गया है। उक्त निर्यात कीमत और समायोजनों के आधार पर निवल निर्यात कीमत संदर्भित की गई है।

पाटन मार्जिन

13. इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से अधिक है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का संबद्ध देशों से पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

14. याचिकाकर्ता ने समग्र रूप से आयातों में वृद्धि, लाभप्रदता में कमी, नियोजित पूंजी पर आय में कमी आदि की दृष्टि से संबद्ध देशों से कथित पाटन के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराये हैं। याचिकाकर्ताओं ने कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के साक्ष्य के रूप में प्रतिकूल कीमत प्रभावों का भी दावा किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन आयातों के कारण याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

जांच अवधि (पीओआई)

15. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जाँच के लिए जांच अवधि 1 अक्टूबर, 2014 से 30 सितम्बर 2015 (12 महीनों) की अवधि का प्रस्ताव किया है। तथापि, प्राधिकारी ने बिल्कुल हाल के आकड़ों का विश्लेषण करने के लिए इसमें 3 महीने का विस्तार किया है इस प्रकार संशोधित पीओआई 1.10.2014 से 31.12.2015 के रूप में है। क्षति जाँच के प्रयोजनार्थ इस अवधि में पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् 2012-13, 2013-14, 2014-15 और जाँच अवधि के आकड़ें शामिल होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों और भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत कर सकता है:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
चौथा तल , जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001**

समय-सीमा

17. इस जाँच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

18. अतः, सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें। घरेलू उद्योग की याचिका पर अपनी टिप्पणियां और प्रश्नावली के अपने उत्तर ज्ञात हितबद्ध पक्षों को अलग से भेजे जा रहे पत्र की तारीखसे 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

19. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

20. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

21. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

22. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

23. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

24. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

25. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2016

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of “Sodium Chlorate” originating in or exported from Canada, People’s Republic of China and EU.

1. **No.14/13/2015-DGAD.**—M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Limited and Teamec Chlorates Limited (hereinafter referred to as ‘petitioner’) have filed an application (also referred to as petition) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Sodium

Chlorate” (hereinafter referred to as subject goods or product under consideration) originating in or exported from Canada, People’s Republic of China and EU (hereinafter referred to as subject countries).

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the dumping and ‘injury’ exists justifying initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The petition has been filed by the petitioner i.e. M/s Gujarat Alkalies(GACL) and Chemicals Limited and Teamec Chlorates Limited (TCL) (hereinafter also referred to as the domestic industry), as producers of the subject goods in India. Petitioners are the only two producers of the subject goods in India.
4. It is also noted that petitioners have neither imported the product under consideration, nor are they related to an importer or exporter of the product under consideration. The petition has therefore been made by and on behalf of the domestic industry and it satisfies the requirements of ‘standing’ under Rule 5 of the AD Rules. Further, the Petitioners constitute ‘Domestic Industry’ in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

Product under consideration

5. The product under consideration in the present petition is "Sodium Chlorate", an inorganic compound with the chemical formula NaClO₃. Sodium Chlorate is a white crystalline hygroscopic powder readily soluble in water. It decomposes above 300 °C to oxygen and sodium chloride.
6. The normal commercial unit of measurement for the product under consideration is kilograms. It is quoted on the basis of weights, and sold in kilograms or MT universally.
7. Subject goods are classified under Chapter 28 of Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 2829 11 00. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the proposed investigations

Like Articles

8. The petitioner has claimed that the product manufactured by the domestic industry and the subject goods imported into India from the subject countries are like articles within the meaning of the Anti-dumping Rules. There is no known difference between the subject goods imported from the subject countries and that produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The consumers can use and are using the two interchangeably and are technically and commercially substitutable. After examination, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to that imported from the subject countries. Therefore, for the purpose of present investigation the subject goods produced by the applicant in India are being treated as like article to the subject goods being imported from subject countries.

Subject Countries

9. The countries involved in the present investigation are Canada, People’s Republic of China and EU.

Normal value

10. The petitioners have claimed normal value of the product under consideration in subject countries on the basis of the constructed normal value in accordance with section 9A (1) (C), Customs Tariff Act, 1975. For China, treated as a non-market economy, normal value has been computed on the basis of the cost of production of raw-material, consumables, utilities as per the Indian cost of production and referencing best practices.
11. For European Union and Canada, the power cost prevailing in these countries also appropriately correlated with the least cost of power based on natural gas conversion has been adopted along with conversion costs as per Indian cost of production. The authority has considered the normal value of product under consideration as computed in the subject countries in accordance with rule 9A (1) (c) as a reasonable normal value based on prime facie evidence. The authority has constructed the normal value in according with rule 9 (5) A for. The subject countries.

Export Price

12. The petitioner has claimed export price for product under consideration based on secondary source i.e. IBIS data. Adjustments on export price have been claimed and referenced on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges. The net export price has been referenced on the basis of the above export price and adjustments.

Dumping Margin

13. There is sufficient prima facie evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are higher than the net export prices, prima-facie indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped from the subject countries.

Injury and Causal Link

14. The petitioner has provided evidence regarding material injury as a result of the alleged dumping from subject countries in terms of increase in imports in absolute terms, deterioration in profitability, return on capital employed etc. The petitioner has also claimed adverse price effects evidenced by price depression and suppression. The Authority considers that there is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the petitioners caused by alleged dumped imports of subject goods from the subject countries.

Period of Investigation (POI)

15. The Domestic Industry has proposed the period of investigation for the present investigation as 1st October 2014 to 30th September 2015 (12 months). However, the Authority has extended the same by 3 months thereby considering the modified POI as 1.10.2014 to 31.12.2015, to undertake the analysis on most recent data. For the purpose of injury investigation, the period will cover the data of previous three years, i.e. 2012- 2013, 2013- 2014, 2014 - 2015 and the Period of Investigation (POI).

Submission of information

16. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street
New Delhi – 110001**

Time limit

17. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.
18. All interested parties are therefore advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter regarding the need to impose anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation. The comments to the domestic industry's petition and filing of questionnaire may be done within 40 days of the date of letter being sent separately to the known interested parties.

Submission of Information on Non-Confidential basis

19. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
20. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.
21. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
25. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

27. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority